

## हिन्दी प्रादेशिक समाचार

### आकाशवाणी चंडीगढ़

(तिथि 14 मार्च 2024, समय 1305 (5 मिनट))

केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है। मंत्रालय ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत पहली अप्रैल से जुलाई के अंत तक चार महीने में पांच सौ करोड़ रुपये प्रोत्साहन राशि के तौर पर दिए जाएंगे।

मंत्रालय ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत ई-रिक्शा, ई-कार्टस और एल-5 मोटर वाहन सहित सिर्फ इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन और इलेक्ट्रिक तीन पहिया वाहनों पर ही प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अलावा दिया जाने वाला लाभ उन्नत प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए उन्नत बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों को ही योजना का लाभ मिलेगा।

मंत्रालय ने आशा जताई कि यह योजना इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को तेजी से बढ़ावा देगी। यह योजना देश में इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास और हरित मोबिलिटी को भी गति प्रदान करेगी।

.....  
भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा की छः लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है।

पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह द्वारा जारी सूची के अनुसार, भिवानी-महेंद्रगढ़ से धर्मबीर सिंह, गुरुग्राम से राव इंद्रजीत सिंह और फ़रीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर उम्मीदवार होंगे। ये सभी एक ही निर्वाचन क्षेत्र से मौजूदा सांसद हैं।

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जिन्होंने कल करनाल विधानसभा सीट से इस्तीफा दिया, उन्हें करनाल सीट से लोकसभा उम्मीदवार बनाया गया है।

हाल ही में आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस के पूर्व प्रदशाध्यक्ष अशोक तंवर सिरसा से उम्मीदवार होंगे और दिवंगत रतन लाल कटारिया की पत्नी बंतो कटारिया को अंबाला सीट से उम्मीदवार घोषित किया गया है। क्राबिले गौर है कि स्वर्गीय रतन लाल कटारिया अंबाला से सांसद थे।

.....

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने गत वर्ष बाढ़ से खराब हुई कपास की फसल के लिए 12 ज़िलों के किसानों को 87 करोड़ 95 लाख रुपये की मुआवज़ा राशि जारी की। इन ज़िलों में भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, गुरूग्राम, झज्जर, जींद, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और सोनीपत शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि रबी सीज़न के दौरान हाल ही में हुई ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान की जानकारी अपलोड करने के लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल कल तक खोल दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गत वर्ष 2 लाख 43 हजार 287 एकड़ भूमि का बाढ़ के कारण फसल खराब होने के मुआवज़े के लिए पंजीकरण किया गया था। सत्यापन के बाद 84 हजार 483 एकड़ भूमि पर फसल नुकसान की पुष्टि हुई और 33 हजार 483 किसानों को मुआवज़ा दिया गया है।

उन्होंने कहा कि गत वर्ष बाढ़ से खराब हुई अन्य फसलों के लिए 130 करोड़ 88 लाख रुपये का मुआवज़ा पहले ही जारी किया जा चुका है। इस तरह गत वर्ष के

.....  
केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से कल करनाल में समाज के वंचित वर्गों के लिए आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली अलग-अलग राज्यों के लाभार्थियों से संवाद किया वहीं पीएम-सूरज पोर्टल का शुभारंभ भी किया। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा राजभवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीधे इस कार्यक्रम से जुड़े ।

श्री दत्तात्रेय ने कहा कि पीएम-सूरज पोर्टल का तात्पर्य प्रधानमंत्री-सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जनकल्याण है तथा इसके अंतर्गत रियायती ब्याज दरों पर ऋण सहायता के माध्यम से देश के सामाजिक रूप से लाभ वंचित वर्गों के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

इस कार्यक्रम में सांसद संजय भाटिया ने भी भाग लिया। उन्होंने इस मौके पर करनाल और कुरुक्षेत्र जिलों के विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित किया।

श्री भाटिया ने प्रधानमंत्री को गरीबों का सच्चा हितैषी बताते हुये कहा कि अब धरातल पर लोगों को इन योजनाओं का लाभ मिलने लगा है।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि सरकार सभी नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने कल तीसरी व चौथी स्टेज के कैंसर रोगियों को डिजिटल रूप से वित्तीय सहायता वितरित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कैंसर और 55 अन्य दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दो नई योजनाओं की शुरुआत की। इस मौके पर मंत्री जे.पी दलाल भी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तीसरी व चौथी स्टेज के कैंसर मरीजों को भी प्रति माह तीन हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। कैंसर और 55 अन्य दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित लोग सरल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह वित्तीय सहायता किसी भी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत मिलने वाले लाभ के अतिरिक्त होगी। यह योजना 3 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए लागू की गई है।